सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2023-25

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 16 अंक - 62 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, रविवार 15 दिसंबर 2024 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका की ओर छत्तीसगढ़

डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार भी डबल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता को दोहरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस संकल्प के साथ विकसित भारत की प्रतिबद्धता जाहिर की उसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में भी जनहित कार्यों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। साय सरकार में गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता के तीन कार्यस्तम्भ के जरिए लोगों तक सुशासन का संदेश जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में संचालित योजनाओं का छत्तीसगढ़ को भरपूर लाभ मिल रहा है। केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और उनका लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने में छत्तीसगढ़ लगातार अग्रणी भूमिका की ओर बढ़ रहा है। जिनमें पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पूरे देश में सर्वाधिक 8.46 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे के पात्र 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को भी पक्का मकान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक पीएम आवास योजना ग्रामीण में 1 लाख 74 हजार 585 हितग्राहियों को उनका आवास मिल चुका है। प्रदेश में पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को पीएम जनमन योजना का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के 24 हजार 542 परिवारो को आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा 1 हजार 699 करोड़ की स्वीकृति से 2 हजार 449 किलोमीटर की 715 सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा, जिनसे 777 पीव्हीटीजी बसाहटें लाभान्वित होगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। प्रदेश में लोगों को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, इस उपलब्धि के लिए भारत द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य के 266 सरकारी अस्पतालों को क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी दिया है। छत्तीसगढ़ में 11 लाख 20 हजार से ज्यादा मरीज आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2023 से नवम्बर 2024 तक 883 संविदा पदों पर नियुक्ति भी दी गई है।

डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार भी डबल हो गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित दूरस्थ इलाकों में 103 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बन चुकी हैं, इनमें 616 सड़कों के नवीनीकरण का कार्य भी जारी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ ही छत्तीसगढ़ के 50 लाख परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए 40 लाख परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचा दिया गया है।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ रूपए की मंजूरी भी मिल चुकी है। उरगा-कटघोरा बाईपास, बसना से सारंगढ़ (माणिकपुर) फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट और रायपुर-लखनादोन इकॉनोमिक कॉरिडोर के लिए भी केन्द्र से स्वीकृति मिल चुकी है, 236.1 किलोमीटर की कुल लम्बाई वाले इस कॉरिडोर को 9208 करोड़ रूपए की लागत बनाया जाएगा। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 20 हजार करोड़ रूपए के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 240 ई-बसों की स्वीकृति भी मिली है, ये बसें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में चलेंगी। इस सुविधा से आम लोगों को सस्ती दर में परिवहन की सुविधा मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का दोहरा फायदा पहुंच रहा है, किसान अपनी सुविधा से अधिकतम 5 लाख तक अल्पकालीन कृषि ऋण भी ले सकते हैं। मोदी जी की गारंटी पर मुख्यमंत्री की पहल से छत्तीसगढ़ के किसानों को उनके धान का देश में सबसे उच्चतम मूल्य मिल रहा है।

भाजपा सरकार में रेल नेटवर्क को मिल रही मजबूती

बस्तर और सरगुजा के सुदूर वनांचलों में भी बिछ रही नई रेल लाइनें

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की डबल इंजन की सरकार में रेल नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइन बिछाने की कई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मजबूत हो रहे रेल नेटवर्क से आने वाले समय में न केवल माल परिवहन की सुविधाओं में इजाफा होगा, बल्कि यहां के लोगों को राज्य के भीतर और राज्य के बाहर भी सुविधाजनक यात्रा के कई नए विकल्प मिलेंगे। राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक और अधोसंरचना विकास को भी नई गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार और रेल मंत्रालय के बेहतर समन्वय से राज्य में नई रेल लाइनों के काम द्रुत गति से चल रहे हैं। रावघाट रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत दल्लीराजहरा से अंतागढ़ तक नई बिछी 77 किलोमीटर लाइन पर यात्री ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इस रेल लाइन के दोनों ओर बसे हजारों ग्रामीण अब अपने गांव से ही ट्रेन में बैठकर रोज दल्लीराजहरा, दुर्ग, भिलाई और रायपुर तक किफायती सफर कर रहे हैं। इस रेल लाइन को रावघाट तक बढ़ाने के लिए तुमापाल (ताहोकी) से कोसरोण्डा तक पांच पुल-पुलियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। रेल पटरी बिछाने का कार्य भी प्रगति पर है। कोसरोण्डा से फुलपाड़ एवं फुलपाड़ से रावघाट तक अर्थ वर्क के साथ 21 पुल-पुलियों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। साथ ही 27 पुल-पुलियों का काम प्रगति पर है। सरगीपाल के पास रेलवे स्टेशन के भवन, प्लेटफॉर्म और आवासीय भवन का कार्य भी प्रगति पर है। रावघाट के भिलाई से रेल मार्ग से जुड़ जाने से भिलाई इस्पात संयंत्र को बड़े पैमाने पर लौह अयस्क की आपूर्ति हो सकेगी। साथ ही इस सुदूर क्षेत्र के लोगों को यातायात का एक सर्वसुलभ और किफायती साधन भी उपलब्ध होगा।

बस्तर में के.के. (कोत्तावलसा से किरंदुल) रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना का काम भी तेजी से चल रहा है। इस 446 किलोमीटर लंबे रेल लाइन का 170 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। बस्तर जिले में इसकी लंबाई 92 किलोमीटर और दंतेवाड़ा जिले में 78 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में इस रेल लाइन के 148 किलोमीटर में दोहरीकरण का काम पूर्ण हो गया है, जिनमें बस्तर जिले में आने वाला 92 किलोमीटर और दंतेवाड़ा जिले का 56 किलोमीटर रेल लाइन शामिल है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए रेल परिवहन के समुचित उपयोग पर जोर दे रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से राज्य में कई रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहे हैं। साथ ही कई परियोजनाओं के विस्तार की तैयारी है। 295 किलोमीटर लंबी और 4021 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेल लाइन परियोजना की मंजूरी रेल मंत्रालय से मिल चुकी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक निर्माण कार्यों के लिए अभी 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस रेल लाइन में डोंगरगढ़ से कवर्धा के बीच 12 और कवर्धा से कटघोरा के बीच 15 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में न केवल यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, बल्कि खनिजों के परिवहन और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने कई नई रेल परियोजनाओं पर काम हो रहे हैं। 180 किलोमीटर लंबी कोरबा-अंबिकापुर नई रेल लाइन के सर्वेक्षण और डीपीआर के लिए 16 करोड़ 75 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना से सरगुजा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। गढ़चिरौली-बीजापुर-बचेली तक 490 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए भी सवा 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से सुदूर क्षेत्रों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरडेगा-भालुमुडा के बीच 37 किलोमीटर डबल लाइन परियोजना ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी।

जिन्दा रहने की जद्दोजहद में फंसी दुनिया

श्रीकंचनपथ

रायपुर में एक करीबी मित्र थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनकी किडनी खराब हो गई थी। डायलिसिस चल रहा था। थोड़ा सा भोजन और चम्मच भर पानी पर दिन बीत रहे थे। पत्नी ने किडनी देने का प्रस्ताव दिया। टेस्ट में वे सफल भी रहीं। पर पति ने मना कर दिया। उनका मानना था कि जितनी जिन्दगी लिखी है, जितना साथ लिखा है उसे स्वीकार करना चाहिए। भिलाई में एक अस्पताल सहकर्मी के पिता की तबियत बिगड़ी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों की राय थी कि जीवन संकट में है। एक अंतिम कोशिश की जा सकती है। इसके लिए उन्हें वेंटीलेटर पर डालना होगा। रोगी खुद इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वह अंतिम सांसें परिवार वालों की सोहबत में लेना चाहता था। शिक्षित तटस्थ परिवार था। उन्हें वापस घर ले जाया गया। तड़के उन्होंने दम तोड़ दिया। तब पूरा परिवार उनके साथ जाग रहा था। किसी ने हाथ पकड़ रखा था तो कोई सिर पर हाथ फेर रहा था। कुछ लोग पैरों के पास बैठे थे। दवाओं के असर से वे कोई तकलीफमहसूस नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे सुकून के भाव थे। जिसने जन्म लिया है, उसकी मौत तो एक दिन आनी ही है। वह कितनी खूबसूरत होगी इसका फैसला भी खुद को ही करना होता है। चिकित्सा विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। किसी की आंख, किसी की किडनी तो किसी का लिवर लेकर अपनी जिन्दगी को आगे बढ़ाया तो जा सकता है पर इसकी अपनी कीमत होती है। स्वाभाविक रूप से शरीर किसी भी बाहरी वस्तु को स्वीकार नहीं करता। उसका प्रतिरोध तंत्र घुसपैठिये अंग को स्वीकार नहीं करता है। प्रतिरोध तंत्र को शांत रखने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। ये दवाइयां तब तक चलती रहती हैं जब तक कि प्रत्यारोपित अंग को रोगी का शरीर स्वीकार नहीं कर लेता। ये दवाइयां काफी महंगी होती हैं। अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता। उनका पूरा ध्यान तो ऑर्गन डोनर और प्रत्यारोपण सर्जरी में लगने वाली रकम में लगा होता है। गरीब परिवार के युवाओं को अंग प्रत्यारोपण के लिए सरकारी मदद मिलती है। इसके बाद दवाओं के लिए भी उसे सहायता मिलती है। छत्तीसगढ़ में भी किडनी प्रत्यारोपण के कई मामले सरकारी मदद से हुए हैं। केन्द्र की योजना ऐसे सभी मरीजों को तीन साल तक प्रतिमाह 10 हजार रुपए का अनुदान देने की है। छत्तीसगढ़ के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (सोटो) ने पिछले साल 119 मरीजों की लिस्ट केन्द्र को भेजी थी पर उन्हें अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। इसलिए ट्रांसप्लांट कराने वालों को दवाइयों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब रोगियों के प्राण दोबारा संकट में हैं। सवाल यह उठता है कि ट्रांसप्लांट और दवाइयों का अप्रूवल एक साथ एक पैकेज के तहत क्यों नहीं कर दिया जाता?

खास खबर...

67 वी नेशनल शूटिंग के लिए आज से ट्रायल शुरू

रायपुर। नई दिल्ली व भोपाल में आयोजित 67वीं नेशनल चैंपियनशिप कम्पटीशन के लिए शूटर्स का ट्रायल सेशन छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन द्वारा 15 से 18 दिसंबर तक शूटिंग रेंज माना में किया जा रहा हैं जिसमे छत्तीसगढ़ के शूटर्स के क्वालीफाई स्कोर के साथ उनका टीम चयन किया जायेगा जो की सीधे दिल्ली व भोपाल में होने वाले नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग ले सकेंगे।

बता दें इस ट्रायल टीम का चयन हर साल नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरएआई को भेजा जाता हैं। छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन द्वारा चार दिवसीय इस ट्रायल में छत्तीसगढ़ के शूटर्स को आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा ही साथ ही शूटर्स अपने ट्रायल से अपने शूटिंग के स्कोर से कंपीटिशन की बारीकियों को सिखने का भी मौका मिलेगा।

आज से प्रारंभ हो रहा है खरमास नहीं होंगे मांगलिक कार्य

रायपुर। आज से खरमास प्रारंभ हो जायेगा इसलिए अब शुभ मांगलिक कार्यों पर विराम लग जायेगा। धर्म संवत बताया गया है कि शुभ विवाह व मांगलिक कार्य एक माह तक नहीं होंगे, क्योंकि आज से खरमास शुरू हो रहा है। इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं। पंडितो ने बताया कि पंचांग की गणना के अनुसार 15 दिसंबर से एक माह तक शादी-विवाह सहित सभी मंगल कार्य नहीं होंगे। 16 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे।

16 जनवरी से विवाह के शुभ मुहूर्त सहित अन्य मंगल कार्य शुरू होंगे। बताया जाता है कि जब सूर्य धनु राशि में रहता है, उस समय को खरमास कहते हैं। खरमास में शादी-विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं। 15 दिसंबर से खरमास लग रहा है। इस दिन सूर्य रात 10.19 बजे धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 30 दिनों तक यानी 15 जनवरी तक इसी राशि में रहेंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब खरमास खत्म हो जाएगा। मान्यता है कि इस समय किए जाने वाले कार्यों में स्थायित्व में कमी मानी जाती है। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार या किसी प्रकार की नई शुरुआत पर रोक है। इस दौरान धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना शुभ फल देने वाली मानी जाती है।

उपांशु ने स्कूल गेम्स के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तीरंदाजी में हासिल किया तीसरा स्थान

राजनांदगांव। गुजरात में आयोजित स्कूल गेम्स के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तीरंदाजी खिलाड़ी उपांशु राव ने देशभर से पहुंचे 1200

खिलाड़ियों में से तीसरा स्थान हासिल कर केवल राजनांदगांव ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उपांशु राव के स्कूल नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, आईबी ग्रुप के एमडी बहादुर अली, आईजी दीपक झा, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी मोहित गर्ग ने बधाई दी है।

ज्ञात हो कि राजनांदगांव पुलिस लाइन में पुलिस विभाग एवं अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से उपांशु निःशुल्क तीरंदाजी खेल का प्रशिक्षण ले रहा है । अपनी खेल प्रतिभा और कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उसने इस मुकाम को हासिल किया है। आर्चरी खेल में महंगे आधुनिक उपकरणों की वजह से अधिकांश खिलाड़ी इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इन खिलाडियों की प्रतिभा को तरासने के लिए आईबी ग्रुप द्वारा खिलाड़ियों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। तीरंदाजी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के लिए आईबी ग्रुप ने 10 लाख रुपए की सहायता भी दी है।

बुर्जुग मां को बेटा-बहू करते थे परेशान, आयोग ने दी न्यायालय जाने की सलाह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक व सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती ओजस्वी मंडावी एवं सुश्री दीपिका शोरी ने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आज 295 वी. सुनवाई हुई। रायपुर जिले में 141 वी. जनसुनवाई।

सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया की उसे कार्यस्थल पर अनावेदकगणों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, आवेदिका अनावेदकगणों की संस्था में 15 वर्षों से कार्यरत् है। स्कूल की अध्यक्ष जो आवेदिका से साथ कार्य कर रही थी उसे अनावेदकगणों ने जांच में गडबडी पाये जाने पर कार्य से निकाल दिया, जिसकी सूचना आवेदिका को नही थी। आवेदिका ने बताया कि अनावेदकगणों द्वारा हिसाब मांगने व हस्ताक्षर को लेकर आवेदिका के साथ गाली-गलौच व मारपीट किया और आवेदिका को 1 माह का वेतन भी नही दिया गया। आयोग ने यह निर्देश दिया कि दोनो पक्ष अपने अपने दस्तावेज लेकर आयोग में उपस्थित हो ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

एक प्रकरण के दौरान बुर्जुग आवेदिका ने बताया कि उसका बेटा-बहू उससे दुर्व्यव्हार करते है और आवेदिका के नाम के मकान में ही निवास कर शारीरिक व मानसिक रूप से अत्याचार कर रहे है। आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में दोनो अनावेदक (बेटा-बहू) के खिलाफ आवेदिका घरेलू हिंसा का मामला न्यायालय में दर्ज करवा सकती है व आयोग ने अनावेदकगणों को समझाईश देते हुए कहा कि वह तत्काल आवेदिका के मकान को खाली करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

एक प्रकरण में अनावेदक ने आवेदिका के दोनो बच्चों 2 वर्ष और 4 माह को आवेदिका से छीनकर अपने पास रख लिया था। आयोग के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अनावेदक को बुलाया गया। अनावेदक अपने 2 वर्ष के बच्चे को लेकर उपस्थित हुआ और 4 माह के बच्चे को वह झांसी से 200 कि.मी. दूर अपनी बुआ के पास छोड़ आया है। आयोग की समझाईश पर दोनो पक्ष साथ रहने को तैयार है। अनावेदक को निर्देशित किया गया कि 13 दिसंबर को अपने 4 माह के बच्चे को लेकर आयोग में उपस्थित हो, तब प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि आवेदिका की मां ने मकान उसके नाम पर रजिस्ट्री किया था, लेकिन अनावेदकगण आवेदिका से गुंडागर्दी करते है इसलिए आवेदिका मकान में नहीं रह पा रही है। अनावेदिका का कहना है कि आवेदिका ने अपनी मां से धोखे से रजिस्ट्री करवाई थी। आयोग ने कहा कि आगामी सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सभी अनावेदकगणों को उपस्थित किया जाना अनिवार्य है ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया जिसमें आवेदिका ने बताया कि आवेदिका के नाम के मकान में अनावेदक (पति) रहता है उनकी 23 वर्ष की पुत्री है। आवेदिका ने कहा कि अनावेदक (पति) उससे दुर्व्यवहार करता है। आयोग के सामने भी अनावेदक ने बत्तमीजी से बात किया जिसे आयोग के सदस्यों ने भी देखा। अगली सुनवाई में आवेदिका और अनावेदक को अपनी पुत्री को आयोग में उपस्थित करने को कहा गया, जिससे प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

कृषि विकास के लिए साथ कार्य करेंगे विश्वविद्यालय व अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ

कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ के तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का हुआ समापन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली का ''उच्च, सतत और समावेशी विकास के लिए कृषि का डिजीटलीकरण'' विषय पर तीन दिवसीय 32वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री, नीति निर्माता एवं शोधकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में भारत में आगामी दो दशकों में कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार मंथन किया गया और घटते संसाधनों तथा बढ़ती हुई उत्पादन मांगों के युग में कृषि में डिजीटलीकरण को बढ़ावा देने तथा नवाचार एवं तकनीकी आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर दिया गया।

इस तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न कृषि अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों तथा शोधार्थियों ने अपने शोध पत्रों में कृषि के डिजीटलीकरण के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किये। कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर पोस्टर भी प्रदर्शित किये गये। कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इन क्षेत्रों में संयुक्त रूप से अनुसंधान तथा अध्ययन कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई। छत्तीसगढ़ में कृषि के विकास के लिए भी साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल को कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ द्वारा संघ का आजीवन सदस्य मनोनीत किया गया। सम्मेलन के आयोजन सचिव तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. हुलास पाठक को संघ का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया।

सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. पी.एस. बिरथल ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक देश को अपनी बढ़ती जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व दबावों को सामना करना पड़ेगा। जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों तथा जैव विविधता पर बढ़ते दबाव और उत्पादन मांगों के तेजी से बढ़ने के पूर्वानुमान के साथ कृषि क्षेत्र को इस अंतर को स्थायी रूप से पाटने के लिए परिवर्तनकारी रणनीति अपनाना होगा। समापन समारोह में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ के वरिष्ठा पदाधिकारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशकगण, अधिष्ठातागण, वैज्ञानिक, शोधार्थी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

रायपुर नगर निगम चालू वित्त वर्ष में म्युनिसिपल ग्रीन ब्रांड जारी करने की तैयारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने नगर निगम मुख्यालय भवन में मुम्बई के पीआरपी प्रोफेशनल एज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष गौरव कुटे एवं इन्दौर के मुकुल एंड गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेट्स के संतोष मुच्छाल के साथ रायपुर नगर पालिक निगम की ओर से चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान म्युनिसिपल ग्रीन ब्रांड जारी किये जाने की तैयारी पर चर्चा एवं विचार-विमर्श करते हुए आवश्यक जानकारी ली एवं कार्य को गतिमान करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त अबिनाश मिश्रा ह्ने अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल, कृष्णा खटीक, संयुक्त संचालक वित्त डीके निर्मलकर, जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे, कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा की उपस्थिति में चार्टर्ड अकाउंटेट गौरव कुटे, संतोष मुच्छाल से चर्चा की एवं रायपुर नगर निगम की ओर से म्युनिसिपल ग्रीन ब्रांड जारी किये जाने की तैयारी को गति प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए। नगर निगम रायपुर द्वारा केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए इस वित्त वर्ष म्युनिसिपल ग्रीन ब्रांड जारी करने की तैयारी कर रहा है।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का हो रहा आयोजन

राजनांदगांव। शासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश परब के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकासखंडों में स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान शिविर, मितानिन सम्मेलन, आयुष्मान वयवंदन कार्ड एवं निक्षय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारी एवं विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक को स्थानीय विभागीय समन्वय करते हुए अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का लाभ लेने की अपील की है।

जैन गुरु ने सिखाए जीवन में तनाव प्रबंधक के तरीके

श्रीकंचनपथ न्यूज

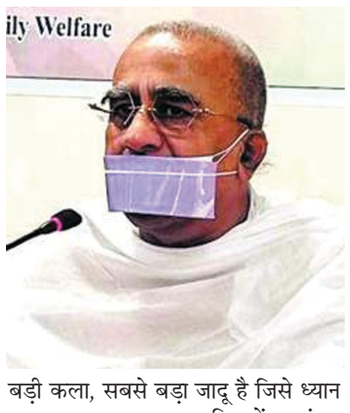

रायपुर। नेहरू मेडिकल कॉलेज में जैन गुरु आचार्य अरविंद मुनि की उपस्थित में तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी, अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर एवं मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और कार्यक्रम संचालक डॉ. अरविंद नेरल भी मौजूद रहे। आचार्य अरविंद मुनि ने चिकित्सा छात्रों एवं चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान ने मनुष्य को इतना सुंदर बनाया है लेकिन तनाव की वजह से वह अपना चेहरा बिगाड़ लेता है।

तनाव यानी टेंशन का मूल कारण समझ में नहीं आ रहा है जबकि इसका मूल कारण मन की चंचलता है। मानव मस्तिष्क में मिनट दर मिनट विविध प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। चौबीस घंटे में से यदि आधा घंटा भी ध्यान करते हैं तो दिन के साढ़े तेईस घंटे निगेटिविटी यानी नकारात्मकता में जा रहे हैं। ईश्वर की आराधना, भक्ति भावना, पूजा-पाठ और नाम सुमिरन के जरिये जीवन में सकारात्मकता आती है। नकारात्मकता को खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय है- ध्यान। अभी करो, अभी पाओ, अभी सीख जाओगे के ध्येय वाक्य के साथ मैं आपको जीवन में तनाव कम करने के लिए ध्यान सिखाने आया हूं। ध्यान सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ा जादू है जिसे ध्यान करना आ गया उस व्यक्ति में असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता आ जाती है। सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रमुख साधन ध्यान है। चाहे कोई भी बीमारी हो, कितना भी कष्ट हो ध्यान से उसे सहने की शक्ति आ जाती है। जिसे ध्यान करना आ गया, उसे सहना आ गया और जिसे सहना आ गया उसे जीना आ गया। उन्होंने ध्यान के चार चरण बताये। पहला महाप्राण ध्वनि जिसमें नाक से सांस लेकर भौंरे की तरह गुंजन करना। दूसरा अनुलोम विलोम की तरह सांस लेते और छोड़ते समय सांसों की गिनती करना। ध्यान के तीसरे चरण में एक हाथ की मुट्ठी बंद करके दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर (तर्जनी अंगुली) को मस्तिष्क के बीचों-बीच रखकर चंद्रमा के प्रकाश का ध्यान करना और ध्यान के अंतिम और चौथे चरण में? शांति का उच्चारण करना बताया। रोजाना दिन में दो बार ध्यान का अभ्यास करने का संकल्प भी दिलाया।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह कार्यक्रम मैंने इसलिए कराया कि जीवन में तनाव नहीं लेना चाहिए। अपने छात्र जीवन के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने फिजिकल केमेस्ट्री से एमएससी किया है। उन दिनों में गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं रहती थी। इसके बावजूद मैंने पढ़ाई के दौरान कभी तनाव नहीं लिया। दबाव या तनाव में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस दौरान उपस्थित प्रोफेसर एवं चिकित्सा छात्रों ने कुछ योगासन भी किए।

चेम्बर कार्यकारिणी समिति की बैठक 17 दिसंबर को

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन 17 दिसम्बर 2024 को दोपहर 12 बजे चेम्बर कार्यालय, चै. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में आयोजित है। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने प्रदेश के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों से अपील की है कि वे बैठक में समय पर अवश्य ही उपस्थित होवें।

छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल महिला संगठन रायपुर जिला इकाई की कार्यकारिणी गठित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल महिला संगठन रायपुर जिला इकाई की प्रथम बैठक संरक्षिका अनिता अग्रवाल एवं प्रांतीय अध्यक्षा गंगा अग्रवाल के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। जिसमें नवनियुक्त रायपुर जिले की अध्यक्षा प्रियंका अग्रवाल ने अपनी टीम का गठन करते हुए सचिव की जिम्मेदारी सारिका खेतान, कोषाध्यक्ष संतोष धनोदीया, मीडिया प्रभारी ज्योति अग्रवाल के अलावा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इस दौरान प्रियंका ने की टीम ने बढ़ते ठंड को देखते हुए निर्णय लिया कि गरीब बच्चों को जल्द से जल्द स्वेटर व मोजा का वितरण किया जाएगा और इसकी शुरुआत वे रामसागर पारा स्थित आवासीय बाल आश्रम से करने जा रहे है।

मीडिया प्रभारी ज्योति अग्रवाल ने बताया ईकाई की प्रथम बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की गई। जिसके तहत रविवार को उनकी टीम सबसे पहले भगवान श्रीराम के दर्शन करने के लिए अयोध्या रवाना होने वाली है। वहां से लौटने के बाद बढ़ते ठंड को देखते हुए रामसागर पारा स्थित आवासीय बाल आश्रम में करीब 100 बच्चों को स्वेटर एवं मोजा का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा उनकी टीम के द्वारा जरुरतमंदों को भी स्वेटर व कंबल का वितरण किया जाएगा ताकि वे इस ठंड से अपने आप को सुरक्षित रख सकें।

ज्योति अग्रवाल ने बताया कि 15 दिसंबर को छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल महिला संगठन रायपुर जिला इकाई के द्वारा अग्रकुल की महादेवी महालक्ष्मी वरदान दिवस का आयोजन अशोका रत्न के मंदिर प्रांगण में मनाया जाएगा। नववर्ष 2025 के स्वागत में महिला संगठन के पदाधिकारी पिकनिक पर जाएंगे। इसके बाद 9 जनवरी 2025 अपना घर एवं वृद्धा आश्रम संगठन की सभी महिलाएं जाएंगी पिकनिक पर जाएंगी। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल महिला संगठन रायपुर जिला इकाई के द्वारा जल्द ही सामूहिक विवाह का आयोजन रायपुर महिला संगठन द्वारा किया जएगा। बैठक में संरक्षिका अनिता अग्रवाल, प्रांतीय अध्यक्ष गंगा अग्रवाल, प्रांतीय महामंत्री निधि अग्रवाल, मीडिया प्रभारी ज्योति अग्रवाल, धार्मिक आयोग से हेमलता बंसल, प्रांतीय सह कोषाध्यक्ष वर्षा अग्रवाल, के साथ ही रायपुर जिले की नवगठित टीम से प्रियंका अग्रवाल, सारिका खेतान, संतोष धनोंदिया, डॉ. नेहा के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्रीकंचनपथ

भिलाई-दुर्ग

ITR फाईल बनवाएं मात्र 499/-

• TDS रिफंड • GST रजिस्ट्रेशन • इनकम TAX फाइल
• प्रोजेक्ट रिपोर्ट • MSME रजिस्ट्रेशन • GST रिटर्न फाइल
• CMA DATE • फूड लाइसेंस • BALANCE SHEET

हमारे TAX EXPERT आपकी मदद हेतु तैयार हैं

संपर्क : शेखर गुप्ता, मो. 93007-55544, 8878655544
D-6 सेक्टर-2, गुरुद्वारा के सामने देवेन्द्र नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ को कभी बीमारू राज्य का दर्जा दिया जाता था। मध्य प्रदेश के समय से ही छत्तीसगढ़ लगातार उपेक्षित रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे बहुत पहले ही भांप लिया था। इसीलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नई राह दिखाने के लिए इसे मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया। हालांकि उस वक्त कठिनाइयां काफी ज्यादा थीं। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर थीं। लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राज्य के बाहर जाना पड़ता था। राज्य में डाक्टरों की कमी थी। मेडिकल कालेज के नाम पर सिर्फ रायपुर ही था जहां से गिनती के डाक्टर ही पास होकर निकलते थे और वो भी अच्छी सुविधाओं की तलाश में राज्य के बाहर निकल जाते थे।

साल 2003 में छत्तीसगढ़ में एक नयी सुबह की हुई और यहां से छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बीते दो दशकों के सफर में आज छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है। कभी जहां सिर्फ एक मेडिकल कालेज हुआ करता था आज इसी राज्य में 10 शासकीय मेडिकल कालेज हैं। एमबीबीएस की सीटें भी 100 से बढ़कर 1460 हो गयी हैं। शासकीय मेडिकल कालेजों में 291 स्नातकोत्तर की सीटें भी बढ़ी हैं जिससे राज्य को विशेषज्ञ चिकित्सक मिल रहे हैं। राज्य के युवा बेहतर डाक्टर बन सकें इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कालेजों में हिंदी में भी पढ़ाई की शुरूआत हो चुकी है। एक वर्ष के दौरान ही छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पदों पर 126 विशेषज्ञ चिकित्सक, 395 चिकित्सा अधिकारियों, 95 स्टाफ नर्स, 35 एएनएम, 29 लैब टैक्नीशियन, 54 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अलावा 149 अन्य पदों पर नियुक्तियां दी गयी हैं।

पहले जहां मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों को एक लाख रूपए के उपर के अति आवश्यक खर्च करने के लिए राज्य शासन से अनुमति लेनी होती थी वहीं आज विष्णु के सुशासन में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रूपए तक की अनुमति प्रदान कर दी है। अब आवश्यक उपकरण, दवाइयां इत्यादि जीवन रक्षक चीजों के लिए मेडिकल कालेजों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि वो खुद ही त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हो चुके हैं। स्वशासी सोसायटियों को वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में शक्तियां आवंटित की गयी हैं ताकि राज्य की जनता को सही समय पर सही इलाज और सुविधा मिल सके।

राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने पहले ही बजट में साय सरकार ने राज्य का स्वास्थ्य बजट 5461 करोड़ रूपए से 38.5 फीसदी बढ़ाकर 7563 करोड़ रूपए कर दिया गया है। पर्याप्त बजट होने से स्वास्थ्य सुविधाओं में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 मे जहां मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख में 269 थी जो आज घटकर 137 हो गयी है।

नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-3 (2005-06) के अनुसार राज्य में संस्थागत प्रसव सिर्फ 15.3 फीसदी था। आज यह लगभग 70 फीसदी का इजाफे के साथ नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-5 (2019-21) के आंकड़ो के अनुसार 85.7 फीसदी तक पहुंच चुका है। वर्ष 2018 की तुलना में आज बस्तर में मलेरिया के मामलों में 50 फीसदी की कमी आ गयी है। 108 संजीवनी एंबुलेंस सेवा राज्य के लोगों के लिए वाकई संजीवनी साबित हो रही है। पिछले एक साल में ही डायल 108 पर 9 लाख 73 हजार 681 आपातकालीन फोन काल्स आए और इनमें से 3 लाख 4 हजार 847 मरीज लाभांवित हुए।

छत्तीसगढ़ की शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राज्य के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है जिसे आने वाले समय में 10 लाख रूपए तक किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत विशेष स्थितियों में इलाज के लिए 25 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत बीते नौ माह में लगभग 1200 लोगों को 43 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। राज्य के पहले डिजिटल बजट में सभी संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोलने का निर्णय लिया गया है और इसकी शुरूआत भी बिलासपुर से हो चुकी है। बिलासपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धनवंतरी दिवस के अवसर पर किया। राज्य सरकार रायपुर के डीकेएस अस्पताल में जल्द ही आर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी देने जा रही है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ये बात भली भांति समझती है कि भारत की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाना है तो स्वास्थ्य वो अनिवार्य कड़ी है जिससे राज्य स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध बनेगा। खुशी की बात ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल बेहद गंभीर हैं। उनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार हो रहा है और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ रहा है।

मुख्यालय में नवनिर्मित वन मंदिर वाटिका का प्रभारी मंत्री ने किया लोकार्पण

बच्चों को प्रकृति और संस्कृति के महत्व के प्रति जागरूक करेगा '' वन मंदिर वाटिका''

- वन एवं पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से वन विभाग का यह प्रयास सराहनीय-प्रभारी मंत्री
- आम के पौधे का भी किया गया रोपण

श्रीकंचनपथ न्यूज

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ शासन के वन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता, तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के दो दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान आज दंतेवाड़ा के टेकनार रोड़ पर बनें देश का पहला वन मंदिर का रिबन काटकर मंत्री केदार कश्यप और विधायक चैतराम अटामी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य रामूराम नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं मुख्य वन संरक्षक आर.सी.दुग्गा, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, डीएफओ सागर जाधव, जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

इस दौरान अनौपचारिक चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में वनों के आध्यात्मिक एवं पर्यावर्णीय को महत्व को प्रमुखता दी गई है। वर्तमान में जबकि आज ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पर पूरी दुनिया में विचार मंथन चल रहा है। उसे देखते हुए वन मंदिर की अवधारणा सराहनीय है। क्षेत्र में निवासरत वनवासी बंधु पीढ़ियों से वनों की रक्षा एवं उसकी संरक्षण के लिए समर्पित रहे है। यहां के जनजीवन का मुख्य आधार वन सम्पदा ही रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन एवं वन विभाग की यह पहल जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रंशसनीय प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि इस वन मंदिर वाटिका में अन्य प्रजाति के पेड़ पौधे लगाकर इसे समृद्ध बनाए। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वृक्षारोपण के तहत ''एक पेड़ मां के नाम'' का संदेश देकर पूरे देश में वृक्षारोपण के महत्व का अलख जगा चुके है। अत: आमजन भी उनके इस अभियान को पूरी तत्परता से गति दें।

उल्लेखनीय है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में बनाये गए वन मंदिर वाटिका में प्रकृति एवं संस्कृति के अनुठे संगम को चरितार्थ किया गया है। वाटिका में प्रवेश करते ही पर्यावरणीय और प्राकृतिक संरक्षण को दर्शाते हुए यहां भारतीय सांस्कृतिक के अनुरूप राशि-ग्रह-नक्षत्र के पौधे, बीमारियों के प्राकृतिक उपचार के लिए योग और औषधि युक्त पौधे की जानकारी देते हुए साइन बोर्ड लगाये गए है। साथ ही क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य पषु पक्षियों एवं तितलियों जैसे जीव जंतुओं की भी सामान्य जानकारी दी गई है। इसके अलावा भगवान श्रीराम के जीवनवृत्त और वनवास काल का भी चित्राकंन वन मंदिर में किया गया है। साथ ही ''रॉक गार्डन'' के तहत इंद्रावती नदी के पत्थर और एनएमडीसी के लौह पत्थरों से भी वाटिका की साज-सज्जा की गयी है। करीब 18 एकड़ में तैयार हुए इस वन मंदिर में 7 थीम के तहत काम हुए हैं। यहां राशि, ग्रह नक्षत्र के पौधे,बीमारियों के इलाज के लिए योग और औषधि (हर्बल पौधे) की जानकारी, सप्तऋषि और पंचवटी वन भी निर्मित किये गए है।

अधिकारियों की मानें तो कि, संभाग का पहला वन मंदिर है। जहां शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मिल पाएगी। इसके निर्माण के लिए अब तक करीब साढ़े 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात करते हुए उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, उनके पसंदीदा विषयों और स्कूल के अनुभवों के बारे में बातचीत की। साथ ही उन्होंने नवनिर्मित वन मंदिर वाटिका के महत्व और इतिहास पर उनके विचार जाने। उन्होंने बच्चों को वन मंदिर वाटिका में रोपे गए धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व के पेड़-पौधों बारे में जानकारी दी उनसे प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की को कहा।

मंत्री ने वन मंदिर में आम के पौधे का रोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने पूरे वन मंदिर का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया और उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन मंदिर को और समृद्ध करने के लिए अन्य प्रकार के पौधों का रोपण भी किया जाए।

जनसंपर्क विभाग की फोटो प्रदर्शनी रही आकर्षण का केन्द

श्रीकंचनपथ न्यूज

राजनांदगांव। राज्य शासन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनादेश परब के अवसर पर राज्य एवं जिले के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा कलेक्टोरेट परिसर में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। फोटो प्रदर्शनी का अधिकारी-कर्मचारियों एवं कलेक्टोरेट में आने वाले जनसामान्य एवं आगंतुकों ने अवलोकन कर शासन की सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टोरेट में जनसंपर्क विभाग की फोटो प्रदर्शनी आकर्षण का केन्द्र बनी है। फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य शासन के विभिन्न जनकल्याकारी योजनाओं, जिले के विकास कार्यों, नवाचार तथा अभियानों के संबंध में झलक प्रस्तुत की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन की विभिन्न लोकहितैषी योजनाओं के माध्यम से जनसामान्य के जीवन में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन को फोटो प्रदर्शनी में संजोया गया है।

अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह ने भी फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने शासन की योजनाओं एवं जिले में चल रहे नवाचार और अभियान के संबंध में एक साथ जानकारी मिलने पर प्रशंसा की। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पदुमतरा निवासी भूमिका कुर्रे ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। उन्होंने फोटो प्रदर्शनी की प्रशंसा की और कहा कि यहां से प्राप्त नि:शुल्क पुस्तके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। जिसमें प्रमाणिक जानकारी एवं तथ्यों का अच्छा संकलन है। डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम चिखलाकसा निवासी श्री राम कुमार ने कहा कि इस फोटो प्रदर्शनी से उन्हें नई-नई योजनाओं की जानकारी मिली है और यह प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी है। ग्राम चिखलाकसा निवासी श्री विमल कुमार ने कहा कि यह राजनांदगांव जिले के विकास कार्य को विशेष तौर पर प्रस्तुत किया गया है। जनसंपर्क विभाग की टीम द्वारा शासन की योजनाओं की जाकनारी दी गई। डोंगरगढ़ के मोहन सिंह ठाकुर ने कहा कि कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। उन्होंने कहा कि फोटो प्रदर्शनी देखकर बहुत अच्छा लगा है। बसंतपुर राजनांदगावं के श्री नितेश कुमार ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन कर शासकीय योजनाओं से संबंधित नि:शुल्क किताब मिलने पर प्रशंसा व्यक्त की। गौरतलब है कि जनसम्पर्क विभाग की फोटो प्रदर्शनी में सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल की अभिव्यक्ति के साथ शासन की विभिन्न योजनाओं जिनमें महतारी वंदन योजना से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और विकास की नई इबारत, किसानों को मिला 2 साल का बोनस, खुशियों का मिला पैगाम, धान खरीदी का महापर्व - कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी, प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला अपना पक्का मकान, पीएमश्री योजना, न्योता भोजन, जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर के हितग्राही हो रहे लाभान्वित, जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जरबेरा, ऑर्किड एवं रंगीन शिमला मिर्च की खेती से समृद्ध बन रहे किसान सहित विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है।

राजनांदगांव जिला मोबाइल अकादमी कोर्स पूर्ण करने में प्रदेश में द्वितीय स्थान पर

श्रीकंचनपथ न्यूज

राजनांदगांव। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल अकादमी कोर्स का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मोबाइल अकादमी कोर्स के तहत राजनांदगांव जिले को प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजनांदगांव द्वारा शत-प्रतिशत मोबाइल अकादमी कोर्स पूर्ण करने पर सभी विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। कलेक्टर ने कहा कि जिले में सभी के सामूहिक प्रयास से यह सफलता मिली है। जिले की ओर से नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जंघेल, जिला प्रबंधक डाटा श्री अखिलेश कुमार चोपड़ा, जिला डाटा सहायक श्रीमती प्रीति सिंह एवं सचिवालय सहायक श्री रवि मेश्राम ने प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्राप्त किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरत्न ने बताया कि जिले में मितानिनों के लिए मोबाईल अकादमी कोर्स का संचालन किया जा रहा है। मोबाइल अकादमी कोर्स संपादित करने में राजनांदगांव जिला देश एवं प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा है। कोर्स पूर्ण करने से सभी मितानिनों के कौशल एवं कार्य करने की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है तथा कार्य करने में आसानी हुई है। मोबाइल अकादमी कोर्स मितानिनों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया मोबाइल पर आपसी संवाद ट्रेनिंग कोर्स है, जो नि:शुल्क है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मितानिनों को 14 पाठ सुनने होते हैं और 11 बार सवाल जवाब देना होता है। यदि 44 में से 22 अंक हासिल प्राप्त करने पर मितानिनों को मोबाइल अकादमी की ओर से एक एसएमएस प्राप्त होता है और सरकार के माध्यम से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। कोर्स पूरा करने से मितानिनों के कौशल में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा मोबाइल अकादमी कोर्स का संचालन किया जा रहा है। जिसमें डॉ. अनीता की आवाज सुनाई देती है, जो पूरी ट्रेनिंग संपादित करती है। इसी प्रकार मोबाइल सुविधा किलकारी जिसके माध्यम से आईवीआर कॉल से सभी गर्भवती माता को उनके गर्भावस्था के दौरान सभी प्रकार की सुविधा हेतु फ्री कॉल से समस्त जानकारी प्रदान की जाती है। सभी गर्भवती माताएं निकट के स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीयन एवं मोबाइल नंबर दर्ज कराकर किलकारी सेवाओं का नि:शुल्क लाभ ले सकतीं हैं। जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के श्री संदीप ताम्रकार ने बताया कि किलकारी मोबाइल सेवा डिजिटल क्रांति से गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं की सेवाओं को बेहतर करने में आसानी हुई है।

सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर छायाचित्र प्रदर्शनी को मिला अच्छा प्रतिसाद

महासमुंद। सरकार गठन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए आज दूसरे दिन अम्बेडकर चौक महासमुंद में जनसम्पर्क विभाग द्वारा छायाचित्र प्रदर्शनी लगाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी, आमजन, महिलाओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रमों की तस्वीरें और जानकारी प्रदर्शित की गई हैं। इसमें प्रमुख योजनाओं में पीएम जनमन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति कमार जाति के हितग्राहियों को दी जाने वाली सेवाएं, और ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

Since 1972
CROWN® - TV
Choice Of Millions
LED Available 16 -20 -22 - 24 - 32-40-50-55-65

Maa Durga Electronics
9827183839
Rohit Electronics
94242-02866
Premier sales: 8959493000
A Leela Electronics: 9425507772
Reena Electronics: 9329132299
Shree Electronics: 7000827361
Authorised Distributers For Chhattisgarh
Trade Enquiry: 98262-52372

संपादकीय

दुरुपयोग के विरुद्ध

सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग की आलोचना करने के साथ ही, इसमें सुधार का सुझाव दिया है। न्यायालय पहले भी अनेक अवसरों पर दहेज विरोधी कानून-भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए या अब नई धारा 86 के दुरुपयोग की बात कह चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग की आलोचना करने के साथ ही, इसमें सुधार का सुझाव दिया है।

न्यायालय पहले भी अनेक अवसरों पर दहेज विरोधी कानून- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए या अब नई धारा 86 के दुरुपयोग की बात कह चुका है। जाहिर है, न्यायिक स्तर पर भी यह बात छिपी नहीं है कि इस कानून का इस्तेमाल प्रतिशोध के लिए होने लगा है। दहेज की शिकायत करके पूरे परिवार को दबाव में लाने की गलत प्रथा गांव-गांव तक पहुंच गई है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफव्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कानून को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बेशक, इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सही जांच की जरूरत होती है, पर शायद यह काम पुलिस ढंग से नहीं कर रही है। दहेज के हजारों मामलों में पुलिस वास्तव में सच्चाई का नहीं, बल्कि आरोपों का पीछा करती है और नए-नए मुकदमे बनते चले जाते हैं। अदालत ने भी अफसोस जताया है कि शिकायतों में अक्सर अतिरंजित और निराधार आरोप शामिल होते हैं। दूर के रिश्तेदारों को भी घसीट लिया जाता है।

अदालत ने बिल्कुल सही कहा है कि वास्तविक दोषियों के खिलाफ ही कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। जाहिर है, इसके लिए पुलिस को मुकदमा लिखते या बनाते समय ही सावधानी बरतनी होगी। यह भी शोध का विषय है कि दहेज के झूठे मामलों से निपटने में पुलिस की सफलता का अनुपात क्या है? दहेज के लेन-देन को रोकना जरूरी है और इसी काम के लिए कानून को बहुत कड़ा बनाया गया है और महिलाओं को शिकायत व सुनवाई के लिए पूरी शक्ति प्रदान की गई है। ज्यादातर मामलों में यह कानून महिलाओं की मुक्ति और न्याय सुनिश्चित करता है, पर बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं, जहां इसके दुरुपयोग की वजह से पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो गई। यहां सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा करनी चाहिए। दुरुपयोग की आलोचना के बावजूद न्यायालय ने यह भी कहा है कि 'हम एक पल के लिए भी यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि महिलाओं को चुप रहना चाहिए या जरूरत पड़ने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से बचना चाहिए।' महिलाओं को समझना होगा कि यह कानून पति और उसके परिवार से बदला लेने के लिए नहीं बनाया गया है। कानून महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं कि महिलाएं इस अच्छे कानून के दम पर अन्याय का कारोबार शुरू कर दें। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में दहेज प्रताड़ना के 80 प्रतिशत मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं।

अदालतों ने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जांच के बाद ही गिरफ्तारी की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस मामले में ताजा व्यवस्था दी है, उसमें भी अलग-अलग शहरों में रहने वाले रिश्तेदारों व विवाहित बहनों को आरोपी बना दिया गया था। पुलिस कई बार कहती है कि वह तो कानूनन कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, जबकि न्यायप्रियता और मानवीयता का प्राथमिक परिचय पुलिस को ही देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है कि कानून के दुरुपयोग को शुरुआत में ही रोकना होगा। साथ ही, अब समय आ गया है कि दहेज विरोधी कानून में जरूरी संशोधन किए जाएं, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके।

ट्रंप की ब्रिक्स देशों को धमकी

ट्रंप ने डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने पर ब्रिक्स देशों के उत्पादों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। संभवतः ऐसी घोषणाएं करते समय ट्रंप भूल जाते हैं कि नई भू-आर्थिकी के बीच वे जो कार्ड खेल रहे हैं, वो दोधारी है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ब्रिक्स देशों ने अपने कारोबार को डॉलर से हटाने की कोशिश की, तो वे उन सबके यहां से अमेरिका होने वाले आयात पर 100 फीसदी सीमा शुल्क लगा देंगे। ब्रिक्स में कई ऐसे देश शामिल हैं, जो अमेरिका के घोषित मित्र हैं। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनाडा जैसे सहयोगी देश पर 25 फीसदी सीमा शुल्क लगाने का एलान ट्रंप पहले ही कर चुके हैं। उनका इरादा यूरोपीय देशों पर भी ऐसी कार्रवाई का है। ऐसा लगता है कि ऐसी घोषणाएं करते समय ट्रंप भूल जाते हैं कि नई भू-आर्थिकी के बीच वे जो कार्ड खेल रहे हैं, वो दोधारी है। उसका उलटा असर भी होगा। डॉलर की भूमिका के लिए आज चुनौती पेश आई है, तो उसकी एक वजह यह है कि अपनी उत्पादक क्षमता खोने के बाद अमेरिका बाकी दुनिया के लिए अपरिहार्य नहीं रह गया है।

डॉलर को वैश्विक कारोबार की मुद्रा बनाने में अमेरिकी आर्थिक ताकत का सबसे प्रमुख योगदान था। इससे अमेरिका को ये विशेष सुविधा मिली। इस कारण देश अपने यहां उत्पन्न मूल्य का एक हिस्सा अमेरिका के नियंत्रण में भेजने को विवश हो गया। यह ऐसी ताकत थी, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग कर अमेरिका लंबे समय तक इस विशेष सुविधा को बनाए रख सकता था। लेकिन भू-राजनीतिक और कूटनीतिक मकसदों को साधने के लिए उसने इस ताकत का अनियंत्रित दुरुपयोग शुरू कर दिया। नतीजतन, उससे प्रतिबंधित देशों की उसकी सूची लंबी होती चली गई। लाजिमी है, प्रतिबंधित एवं प्रतिबंधों की आशंका झेल रहे देश विकल्प की तलाश में जुटते। उसका परिणाम फिलहाल अपनी मुद्राओं में अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने के चलन में दिख रहा है। ब्रिक्स ऐसे सामूहिक प्रयास का मंच बना है। चल चुके इस चक्र को रोकना अब कठिन है। ट्रंप प्रतिबंधों की राह छोडने और डॉलर के अंतरराष्ट्रीय भुगतान के मंच स्विफ्ट से किसी देश को बाहर ना करने का एलान करते, तो शायद वे कुछ सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने वही तलवार उठाई है, जिसके इस्तेमाल का नतीजा डॉलर से बचने की परिघटना के रूप में सामने आया है।

(आरएनएस)

नजरिया

जलवायु बदलावों की गति थामने को जरूरी गंभीर पहल

दुनिया में ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग सिर्फ हवा-हवाई बातें हैं। इनका हौवा खड़ा करके कुछ पर्यावरणवादी संगठन और गरीब देश धन ऐंठते हैं। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे ही तर्क देकर जलवायु परिवर्तन थामने वाली पेरिस संधि से बाहर भी हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग का कई बार सकारात्मक असर भी होता है। इसका एक उदाहरण उत्तराखंड में सामने आया, जहां तेजी से बढ़ते एक हिमनद यानी ग्लेशियर का पता चला है।

अभिषेक कुमार सिंह

भारत-चीन सीमा के नजदीक नीति घाटी में पाया गया यह हिमनद 48 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। हाल तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और सिक्किम आदि में हिमनदों के पिघलने, सिकुड़ने और गायब हो जाने की खबरें आती रही हैं। तेजी से बढ़ते ग्लेशियर की सूचना से जलवायु परिवर्तन से जुड़े वे सवाल फिर उठ खड़े हुए हैं कि कहीं सच में ऐसी आपदाओं का फर्जी डर तो नहीं दिखाया जा रहा है। या फिर नुकसान करने की बजाय यह परिवर्तन पृथ्वी के वातावरण में संतुलन बनाने के लिए तो नहीं होता है।

उत्तराखंड में सामने आए हिमनद का पता देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफहिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने उपग्रही आंकड़ों और अन्य तकनीकों के जरिए लगाया है। क्या ऐसा जलवायु परिवर्तन के सकारात्मक प्रभावों से हुआ है- इसके जवाब में इन भूवैज्ञानिकों का मत है कि यह विचित्र घटना पर्यावरणीय असंतुलन यानी हाइड्रोलॉजिकल इंबैलेंस का परिणाम है जिसकी वजह से बर्फ की परतें कमजोर हो जाती हैं और वे अस्थिर होकर बड़े इलाके में फैल जाती हैं। बाढ़, सूखे, चक्रवात, भीषण गर्मी या सर्दी समेत तमाम तरह के मौसमी असंतुलन भी जलवायु परिवर्तन की अराजकताओं के नतीजे में पैदा होते हैं। बीते वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर कई यूरोपीय देशों ने जैसी भीषण गर्मी और बाढ़ की त्रासदियां झेली हैं, उनमें यह असंतुलन दिखाई दे रहा है। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस बयान दे चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गंभीर किस्म की जलवायु अराजकता की ओर बढ़ रही है।

जलवायु संकटों पर निगाह डालें तो बीते कुछ वर्षों में दुनिया में काफी उथल-पुथल हो गई। हाल के

चार वर्षों में कोरोना वायरस के कारण लगे प्रतिबंधों का धरती की जलवायु पर सकारात्मक असर हुआ था। तब उम्मीद की जाने लगी थी कि इन सार्थक तब्दीलियों से सबक लेते हुए पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्थाएं विकास का ऐसा रास्ता चुनेंगी, जिसमें धरती के सुंदर भविष्य की परिकल्पनाएं साकार हो जाएंगी। लेकिन पहले तो अमेरिका-चीन के बीच तनातनी ने माहौल बिगाड़ा व बाद में रूस-यूक्रेन जंग ने। विशेषज्ञों का दावा है कि पिछले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (ग्लासगो) में जिन बातों को लेकर सहमति बनी थी, उन्हीं की दिशा में बहुत धीमी प्रगति हुई। दूसरी वजह वित्तीय संकट और ऊर्जा के वैश्विक विकल्पों के सीमित होने की घटनाओं से बनी। ये घटनाएं न होतीं तो संभवतः जलवायु परिवर्तन लक्ष्य हासिल करने की राह आसान होती।

विकास बनाम पर्यावरण संकट के रिश्तों की बात करें तो तय है, जैसी धरती हमें सदियों पहले मिली थी, वह हमेशा वैसी नहीं रह सकती। विकास की कुछ कीमत पर्यावरण को अदा करनी ही थी। लेकिन धरती और इसकी आबोहवा औद्योगिक क्रांति के डेढ़ सौ बरस में ही इतना ज्यादा बदल गयी कि वैसा कुछ पृथ्वी पर जीवन के विकास के हजारों साल में कभी नहीं हुआ। चार दशक पहले जिनेवा मेंआयोजित पहले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से मिलती है, जिसमें जुटे विज्ञानियों ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे मौसमी बदलावों पर औपचारिक रूप से चिंता जताई थी। हाल के वर्षों में जलवायु विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अब अगर जल्द ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बनाई गई तो इंसान नामक प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा हो सकता है क्योंकि क्लाइमेट इमरजेंसी का वक्त आ पहुंचा है। इसका अंदाजा वर्ष 2022 में पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ व यूरोप के कई देशों में ऐतिहासिक गर्मी पड़ने से नदियों के सूखने से लगता है। जलवायु परिवर्तनों के बदलावों को कई वैज्ञानिक अध्ययनों में दर्ज किया गया है।

ब्रिटेन विश्व में ऐसा पहला देश है जिसने पांच साल पहले 1 मई, 2019 को लंदन में हुए एक आंदोलन के बाद प्रस्ताव पारित करते हुए देश में सांकेतिक तौर पर जलवायु आपातकाल घोषित किया था। मई 2019 में ही आयरलैंड ऐसा करने वाला दूसरा देश बना था जिसकी संसद ने 'जलवायु आपातकाल' घोषित कर दिया था। साथ ही संसद से आह्वान किया था कि आयरिश सरकार जांच करके पता लगाए कि उसकी कौन सी नीतियों के कारण जैव-विवधता को नुकसान पहुंच रहा है और भरपाई के लिए क्या बदलाव किए जाएं। जलवायु आपातकाल लगाने के फैसले के पीछे लंदन में हुए जिस आंदोलन की भूमिका है, उसे वहां जिस समूह ने चलाया था उसका लक्ष्य साल 2025 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सीमा शून्य पर लाने और जैवविविधता के नुकसान को समाप्त करना है। दरअसल पृथ्वी का हम इंसानों ने बेदर्दी से दोहन किया है। रिपोर्टों के मुताबिक, पृथ्वी के वायुमंडल में पहले से ज्यादा जहरीली गैसें और गर्मी घुल गई है। कोई अपवाद छोड़ दें तो इस गर्मी के चलते गंगोत्री और अंटार्कटिका जैसे ग्लेशियर तेजी से पिछल रहे हैं। तितलियों, मधुमक्खियों, मेंढक व मछली प्रजातियों, चिड़ियों, दुर्लभ सरीसृपों और अन्य जीव-जंतुओं की सैकड़ों किस्में हमेशा के लिए विलुप्त हो गई हैं। जंगल खत्म हो गए हैं, पानी का अकाल पड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है जिससे सांस लेना दूभर हो गया है। नदियों से भी आस टूट रही है। नदियों के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है।

चार-पांच दशकों में धरती की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि आह्वान कई बार किए जा चुके हैं। अरबों-खरबों के खर्च के बावजूद वे कोशिशें रंग लाती नहीं दिखीं, जिन पर अमल होने से धरती माता के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार आ जाना चाहिए था।

(ये लेखक के विचार हैं)

एक निर्दयी शासन का अंत दूसरे निर्दयी शासन को जन्म

श्रुति व्यास

मनमानी और लोगों को दबा कर शासन करने वालों का राज एक न एक दिन खत्म होता ही है। और जब उनके राज का अंत होता है तो वह निष्ठुर होता है। और उन देशों में भी जहां लोकतंत्र दिखावे का है। हाल के दशकों पर निगाह डालें। शेख हसीना का क्या हुआ? सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, जीन अल अबिदीन बेन अली, होस्नी मुबारक आदि की सूची में अब बशर अल-असद का नाम भी जुड़ गया है।

असद परिवार के पचास साला राज के खात्मे का सभी और स्वागत है। सीरिया में लोगों ने राहत की सांस ली। वहां एक नई शुरूआत' और बाकी दुनिया से नए सिरे से संबंध कायम करने को लेकर जश्न का माहौल है। पश्चिम ने असद सरकार के तख्तापलट पर अपनी प्रसन्नता और हर्ष बेबाकी से जाहिर की है। लेकिन एक ऐसे देश के लिए नई शुरूआत कैसी होगी जिसने सिर्फ निर्ममता भुगती है? वे एक नई शुरूआत कैसे करेंगे जबकि उन्होंने जीवन भर सिर्फ दमन देखा-भोगा है? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस्लामिक उग्रवादियों और आतंकवादियों का गठबंधन ताजी शुरूआत' का प्रतीक भला कैसे बन सकता है? भविष्य में वे क्या करेंगे यह कोई नहीं जानता। ऐसे में क्या इनके सत्ता पर काबिज होने का जश्न मनाया जाना चाहिए?

दस साल पहले मिस्र, लीबिया, टयूनीशिया और यमन-जहां तानाशाहों का तख्ता पलट दिया गया था -में खुशियां मनाई गईं थीं और सुनहरे, आजादी भरे दिनों का इंतजार था। उम्मीदों का कोई ठिकाना न था। सारी दुनिया ने तानाशाहों का राज खत्म होने की थी। ये चार देश क्रांति की सफलता की नजीर बन गए थे। उसे अरब स्प्रिंग कहा गया था। लेकिन आज इन देशों में जो हालात हैं वे हमारे लिए एक चेतावनी हैं।

मिस्र में लोकतंत्र अधिक समय तक कायम न रह सका। लीबिया, टयूनीशिया और यमन गृहयुद्ध में फंस गए। ये विदेशी ताकतों का अखाड़ा हुए। खाड़ी के अमीर देशों ने वहां अपने लोगों को सत्ता पर काबिज कराने और अन्य देशों में अलोकतांत्रिक शक्तियों की मदद के लिए बेशुमार पैसा खर्च किया। आज इस क्षेत्र में 2010 से भी कम आजादी है -और ज्यादातर पैमानों पर इन देशों के हालात खराब ही हैं। लोकतंत्र के झंडाबरदार पश्चिमी देश, इन देशों की नई शुरुआत में मददगार नहीं हुए। जैसा कि अफगानिस्तान के मामले में हुआ, अब वे इस सोच-विचार में डूबे हुए हैं कि उन देशों में बगावत को सफल बनाने के लिए वे क्या कर सकते थे। क्या इससे ज्यादा आत्ममुग्ध होना संभव है?

जो हुआ उसकी वजह बहुत और सीधी

है। बगावत के बाद ईरान से रूस तक, और पश्चिम देशों से लेकर तक क्षेत्रीय ताकतों तक ङ्क सभी इन देशों में अपना दबदबा कायम करने में जुटे। इसके अलावा, इस्लामवादी समूह भी सक्रिय थे जो चाहते थे कि उनकी मर्जी चले और सत्ता पर उनका प्रभाव रहे। लेकिन सबसे बड़ी भूल हालातों को समझने में हुई। लोकतंत्र के लिए मात्र यह पर्याप्त नहीं होता कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हों। उसके लिए बातों को समझने, जानने और उनमें रूचि लेने वाले नागरिकों, सभी पक्षों को स्वीकार्य नियम-कानूनों और इस सांझे भरोसे की भी जरूरत होती है कि राजनैतिक मतभेद देश के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बनेंगे।

सीरिया पर असद का राज खत्म होना एक राहत भरी खबर है लेकिन अनिश्चितता के हालात हैं। इस्लामिक उग्रपंथियां का गठबंधन एक बड़ा खतरा है। हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस), जिसकी इस तख्तापलट में सबसे बड़ी भूमिका थी, काफी शक्तिशाली है। अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। देश में अपना दबदबा कायम करने के लिए एचटीएस को एक अन्य तुर्की-समर्थित संगठन, जिसका प्रभाव क्षेत्र उत्तरी सीरिया है, और कुर्दिश नेतृत्व वाले पूर्वी सीरिया के एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है, से निपटना होगा।

हालांकि एचटीएस अपनी छवि एक उदारवादी और नर्मदिल संगठन की बनाने की कोशिश कर रहा है, जो ईसाईयों, ड्रूसों और असद के समर्थन के मुख्य आधार शिया समुदाय के अलावतियों समेत सीरिया के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा जब असद के बाद के दौर के सीरिया के शासन के संचालन के संबंध में इन समुदायों के साथ इस संगठन का कोई समझौता हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो गृहयुद्ध चलता रहेगा क्योंकि विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के लडाके, नई केन्द्रीय सरकार को अपने-अपने इलाकों में घुसने से रोकने के लिए खड़े हो जाएंगे।

जहां तक विदेशी शक्तियों का सवाल है, तुर्की ने अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। तुर्की, सीरिया में राजनैतिक स्थिरता इसलिए भी चाहता है क्योंकि तुर्की में रह रहे 30 लाख सीरियाई शरणार्थी तब तक अपने देश वापिस नहीं जाएंगे जब तक वहां से असद का नामोनिशां मिट नहीं जाता। राष्ट्रपति अर्दोगान को शरणार्थियों को वापिस भेजने में असफल रहने के लिए देश में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तुर्की किस सीमा तक एचटीएस को अपने नियंत्रण में रख सकेगा, यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। अर्दोगान का एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल-जोलानी पर कितना प्रभाव है, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ईरान और रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी और वे कौन-से कदम उठाएंगे, यह समय बताएगा। ईरान का मानना है कि एचटीएस के सशक्त होने और आगे बढ़ने में इजराइल और अमेरिका का मुख्य योगदान रहा है। उसका दावा है कि इजराइल इस संघर्ष का लाभ उठाकर सीरिया के रास्ते ईरान से लेबनान पहुंचाए जाने वाले हथियारों के मार्ग को बंद करना चाहता है। यह बात सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर कही जा रही है, खासकर शियाओं द्वारा। सीरिया का घटनाक्रम निश्चित ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा।

असद परिवार का राज खत्म होना उतना ही बुरा है जितना उनका शासन था। इसलिए दुनिया को और बुरे हालातों के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया के इस इलाके में अनिश्चितता है और कष्टपूर्ण हालात हैं। कुछ देश पूरी तरह असफल हो चुके हैं और कुछ ऐसे है जो अपनी युवा आबादी को बेहतर भविष्य देने में सक्षम नहीं हैं। बगावतें, कामयाब कम होती हैं और नाकामयाब ज्यादा। वे अक्सर चार दिन की चांदनी साबित होती हैं। पश्चिम एशिया में एक निर्दयी शासन का अंत दूसरे निर्दयी शासन को जन्म देता है ङ्क जो उतना ही या उससे ज्यादा बर्बर होता है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, उम्मीद और समृद्धि इस क्षेत्र को रास नहीं आते।

(ये लेखक के विचार हैं)

अवैध प्रवेश की कोशिश में बढ़ोतरी

कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध प्रवेश की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या में अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 22 फीसदी बढ़ोतरी हुई थी। कनाडा के रास्ते ऐसे कुल 1,09,535 प्रयास हुए, जिनमें 16 प्रतिशत में भारतीय शामिल थे। गुजरे हफ्ते राज्यसभा में इस प्रश्न का विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जवाब नहीं दिया कि क्या भारत से गैर-कानूनी ढंग से बाहर जाकर आश्रय मांगने वाले लोगों की संख्या में 800 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। सिंह ने कहा कि सरकार के पास इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये लोग जिन देशों में जाते हैं, वहां की सरकारें उन्हें साझा नहीं करतीं। मगर उन्होंने यह जरूर कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे देश की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं।

बहरहाल, अब एक आंकड़ा जरूर सामने आया है, जिसे भारत सरकार के नजरिए से देश के लिए अपमानजक कहा जाएगा। ये सूचना अमेरिका के कस्टम और सीमा सुरक्षा विभाग ने दी है। उसके मुताबिक कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध प्रवेश की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या में अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 22 फीसदी बढ़ोतरी हुई थी। कनाडा के रास्ते ऐसे कुल 1,09,535 प्रयास हुए, जिनमें 16 प्रतिशत में भारतीय शामिल थे। उसके पहले वाले वर्ष में 30,010 भारतीयों ने ऐसी कोशिश की थी, जबकि उपरोक्त अवधि

में यह संख्या 43,764 हो गई। और यह सिर्फ कनाडा के रास्ते हुए प्रयासों का आंकड़ा है और वह भी सिर्फ उनसे संबंधित है, जिन्हें ऐसी कोशिश करते हुए पकड़ा गया। अमेरिका में ऐसी घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिशें मेक्सिको की तरफ से होती है।

अब चूंकि अवैध आव्रजकों को देश से निकालना और अवैध आव्रजन रोकना निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो यह मुद्दा चर्चा में आया है। वैसे भारत से बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से जाकर विदेश में बसने की कोशिश कर रहे हैं, यह आम जानकारी है। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी कोशिशों अक्सर साधन संपन्न वर्ग के लोग शामिल होते हैं। क्यों? मान-अपमान की सोच से बाहर निकल सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आखिर क्यों विदेश में बसाने के लिए 80 लाख रुपये तक एजेंटों को देने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं? देश में मौजूद अवसरों के प्रति लोगों का विश्वास इतना क्यों डोल गया है, सोचने का मुद्दा यह है।

(आरएनएस)

खास खबर

ड्यूटी पर जा रहे जवान की सड़क हादसे में मौत

धमतरी। धमतरी के अर्जुनी चौके पास हुए सड़क हादसे में पुलिस जवान की मौत हो गई है। बाइक सवार जवान को अज्ञात वाहन ने अपनी अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार जवान हेलमेट पहना हुआ था फिर भी उसके सिर के कई टुकड़े हो गए। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार भखारा थाना में आरक्षक के पदस्थ संबलपुर निवासी केशव मुरारी शनिवार सुबह पुलिस का जवान ड्यूटी में जा रहा था। जवाना अपनी बाईक से जा रहा था इसी दौरान अर्जुनी चौक रलायंस पेट्रोल पंप के पास एक टेंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जवान को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में जवान का सिर टेंकर के पहिये के नीचे आ गया और बुरी तरह कुचल गया। जवान इस दौरान हेलमेट पहना हुआ था उसके बाद भी उसके सिर के कई टूकड़े हो गये और मौके पर ही जवान केशव की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसें के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और इसकी सूचना अर्जुनी पुलिस को दी गई।

किसान से रिश्वत मांगने वाला पटवारी निलंबित

कवर्धा। किसान से रिश्वत की मांग करने वाले पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है. बता दें कि पटवारी पर कार्रवाई का मांग को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। इस दौरान छात्र नेता और एसडीएम से झूमाझटकी भी हुई थी। इसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की है। रिश्वत मांगते हुए पटवारी का आडियो क्लीप भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कवर्धा कलेक्टर ने डोंगरियाकला के हल्का नंबर 43 के पटवारी डोमन लाल साहू को निलंबित कर दिया है।

पर्स एवं मोबाईल लूट के मामले में लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौपाटी के पास से वर्ष 2019 में हुए पर्स एवं मोबाइल लूट के मामले में लम्बे अरसे से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियो के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में धारा 379, 356, 34 भादवि. के तहत् कार्यवाही की गई है मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 16.03.2019 को महेन्द्र पाण्डेय ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी दो बहनें दिनांक 15.03.2019 को अपने स्कूटर वाहन में तेलीबांधा चौपाटी से वापस अपने घर आ रही थी तभी भारत माता चौक के पास पल्सर वाहन सवार दो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हाथ में रखे पर्स को झपट्टा मारकर उसमें रखे मोबाइल, एटीएम एवं पेनकार्ड को लेकर भाग गये थे। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 379, 356, 34 भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस.पास लगे सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर भी लगाये गये इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली और आरोपी की पहचान राहुल द्विवेदी नामक व्यक्ति के रूप में किया गया। पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त घटना को अपने साथी पंकज कौशल के साथ मिलकर अंजाम देना स्वीकार किया।

दो बड़े शातिर साइबर ठग गिरफ्तार करोड़ों रुपए की इनवॉइस जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर साइबर पुलिस ने दिल्ली के दो बड़े शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी दिल्ली से रायपुर में आकर रह रहे थे। आरोपियों अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा कर रायपुर में दो फर्जी कंपनियां खोल रखी थी। इसी आधार पर आरोपियों ने अलग-अलग बैंकों में करीब 30 प्लेटिनियम अकाउंट भी खुलवाये थे। पुलिस ने इनके कब्जे से थाईलैंड, हॉन्गकॉग भेजे गए 12083998 यूएस डॉलर (102.4 करोड़ रुपए) की इनवॉइस जब्त की है। साथ ही 175 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 2 करोड़ से अधिक की रकम भी साइबर की टीम ने होल्ड करवाया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी डॉक्टर प्रकाश गुप्ता ने उनके साथ शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के नाम से 11 लाख ठगी होने पर थाना आमानाका में सूचना दिया था। रिपोर्ट पर धारा 420,34 पंजीकृत कर विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी। विवेचना क्रम में तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए। पता चला कि आरोपी पवन और गगनदीप दोनों दिल्ली के निवासी हैं। दोनों आरोपी रायपुर छत्तीसगढ़ आकर अपने आधार कार्ड में रायपुर का पता बदलवाए तथा उसी पता के आधार पर दो फर्जी कंपनी फ्रिज टैक सोल एवं जीपी इंटरप्राइजेस बनाकर अलग अलग बैंकों में 30 प्लेटिनियम अकाउंट खोले। उक्त बैंक अकाउंट का प्रयोग ठगी से प्राप्त रकम से यूएस डॉलर खरीद कर हॉन्गकांग की 4 कंपनी हाइपरलिंक इंफोसिस्टम लिमिटेड, ब्लू ऑर्किड ग्लोबल, कंसाई इंटरनेशनल लिमिटेड, एम एस मॉर्निंग तथा थाईलैंड की 4 कंपनी एनआरआई सिस्टम टेक्नो, परसौल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल विजार्ड टेक्नोलॉजी, डाटा आर्ट टेक्नोलॉजी को यूएस डॉलर भेजते थे। उक्त हॉन्गकांग और थाईलैंड की कंपनियां के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, ये कंपनियां वहीं संचालित हैं जहां डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड एवं अन्य साइबर अपराधों से संबंधित आईपी की जानकारी मिली है। आरोपियों से पूछताछ में लुधियाना, दिल्ली की कंपनी की जानकारी मिली है, जिस पर कार्यवाही जारी है। दोनों आरोपियों से 41 बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, चेक बुक, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल, डॉलर परचेस इनवॉइस, वन टाइम पासकोड डिवाइस, यूपीआई स्कैनर अलग-अलग एड्रेस के आधार कार्ड जप्त हुए हैं। आरोपियों के विरुद्ध वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में रिपोर्ट दर्ज है। आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जारी है।

मामले में पुलिस ने पवन कुमार पिता सुखबीर सिंह, उम्र 40 वर्ष, गुरु हरकिशन नगर, मटियाला एक्सटेंशन, उत्तम नगर दिल्ली तथा गगन दीप पिता दर्शन लाल उम्र 44 वर्ष, विकासपूरी एक्सटेंशन दिल्ली को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से हॉन्गकांग और थाईलैंड भेजे गए 12083998 यूएस सडॉलर (102.4 करोड़ रुपए) की इनवॉइस जप्त किया है।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

ड्रोन से भेजी जाएगी दवाई और ब्लड सैंपल रायगढ़ से तमनार तक हुआ सफल ट्रायल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है. ड्रोन के जरिए दवा और ब्लड सैंपल भेजने की योजना बनाई गई है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'स्वास्थ्य सुविधाओं में ड्रोन तकनीक का उपयोग' के तहत आज ड्रोन के माध्यम से दवा एवं ब्लड सैंपल रायगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार भेजा गया. महज 15 मिनट में सफलतापूर्वक परीक्षण कर रिपोर्ट भेज दी गई।

रायगढ़ कलेक्टर निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. बीके चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में मिनी स्टेडियम रायगढ़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार हाईस्कूल मैदान तक ब्लड सैंपल और दवा भेजने का सफल ट्रायल किया गया. ड्रोन से वांछित स्थल तक दवा पहुंचाने के सफल ट्रायल से स्कूली बच्चों और स्वास्थ्य कर्मियों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला.

बीएमओ डॉ. डीएस पैकरा ने बताया कि रायगढ़ से ड्रोन दवा लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार हाई स्कूल मैदान में सुरक्षित लैंडिंग की. इसके बाद ड्रोन से दवा सामग्री उतारा गया और स्वास्थ्य केंद्र से रक्त सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया।

छत्तीसगढ़ में लगा साल का आखिरी लोक अदालत

साढ़े 4 लाख से अधिक मामले सुलझाए गए, 536 श्रमिकों को मिला न्याय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। साल 2024 के आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय रायपुर में शनिवार को आयोजित किया गया। नेशनल लोक अदालत में कुल 4,58,085 प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं, नेशनल लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अशोक कुमार साहू, जिला एवं सत्र के जज और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हितेन्द्र तिवारी ने नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया।

छत्तीसगढ़ जूट इंडस्ट्री रायपुर में आवेदक और 535 अन्य श्रमिक कई साल से काम कर रहे थे। जिन्हें प्रबंधन ने उद्योग में अस्थायी काम बंद कर नौकरी से निकाल दिया था। रोजगार छिनने के कारण श्रमिक और प्रबंधन के बीच विवाद हो गया। उप श्रमायुक्त ने पाया है कि छत्तीसगढ़ जून इंडस्ट्रीज ने नियमानुसार शासन से पूर्वानुमति लिए बिना की गई अस्थायी हड़ताल वैधानिक, उचित और श्रमिक राम सिंह और अन्य 535 श्रमिक सहायता के पात्र हैं। इस मामले में निर्णय के लिए प्रकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 के अंतर्गत श्रम न्यायालय रायपुर को भेजा गया।

समझौते के बाद दिया गया चेक: पीठासीन अधिकारी विभा पाण्डेय के श्रम न्यायालय में समझौते के आधार पर प्रकरण के निराकरण के लिए पेश किया गया। आवेदक रामसिंह और 535 श्रमिक की ओर से अधिकृत 10 प्रतिनिधियों ने प्रबंधन के साथ समझौता किया। शनिवार को 46 श्रमिकों को जिला न्यायाधीश और विभा पांडेय पीठासीन अधिकारी ने 24 लाख 43 हजार 693 रुपए का चेक दिया। बाकी 120 दिन के अंदर बाकी भुगतान भी पूरा कर लिया जाएगा।

न्यायालय के समझाइश पर पति-पत्नी हुए एक: आवेदिका ने अनावेदिका अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण का प्रकरण इस आधार पर पेश किया था कि, अनावेदक दहेज की मांग लेकर उसके साथ मारपीट और लड़ाई-झगड़ा कर घर से निकाल दिया। इसलिए वो मायके में रहती है। अनावेदक रायपुर में डेली नीड्स की दुकान का संचालन कर 50 हजार रुपए कमाता है। इसलिए उसने अपने भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह 20 हजार रुपए मांगे।

अनावेदक पति ने बताया कि, वो दहेज की मांग नहीं किया और ना ही मारपीट किया। वो अपनी पत्नी को रखना चाहता है। बिलासपुर हाईकोर्ट में आवेदिका के द्वारा क्रीमिनिल रिविजन पेश किया गया था। जहां राजीनामा का प्रयास किया गया। कुटुम्ब न्यायालय ने दोनों पक्षों को समझाइश दी। जिसके बाद साथ में रहकर अपने दाम्पत्य जीवन जीने के लिए राजी हुए।

पिकअप वाहन पलटने से 12 घायल, 4 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर

बलरामपुर। जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के रमडोल और चाकी के बीच पिकअप वाहन पलटने से लगभग एक दर्जन लोग घायल हुए है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को प्राथमिक उपचार के लिए रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां डॉक्टरों ने बेहरत इलाज के लिए बलरामपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

पुलिस के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामचंद्रपुर विकासखंड के विशालपुर ग्राम से मितगई खिलाड़ी फुटबॉल खेलने के लिए पिकअप वाहन से जा रहे थे, तभी रमडोल और चाकी के बीच ट्रक से साइड लेने के दौरान अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गई। जिसमें लगभग एक दर्जन खिलाड़ी घायल हो गए। जिसमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने खिलाड़ियों को प्राथमिक उपचार के लिए रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आई। जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया।

पिकअप और ड्राइवर की तलाश जारी है विजयनगर चौकी प्रभारी अश्विनी सिंह ने बताया कि इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अग्रिम विवेचना की जा रही है। पिकअप वाहन जब्त कर ड्राइवर की तलाश में लग गए है।

समर्थन मांगने किसानों ने किया मार्च

राजनांदगांव। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत प्रदेश किसान संघ द्वारा 16 दिसंबर को राजधानी में आयोजित प्रदर्शन एवं अपनी मांगों के लिए समर्थन जुटाने जन समर्थन अपील मार्च किया गया एवं पर्चे बांटे गए। उल्लेखनीय है कि केन्द्र द्वारा 117 रू. समर्थन मूल्य का लाभ देते हुए 3217 रू. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया चौथी किश्त का भुगतान एवं धान खरीदी व्यवस्था में सुधार कर पूरे तीन महिने धान खरीद की मांग को लेकर प्रदेश किसान संघ लगातार आंदोलन चला रहा है। घर-घर चिट्ठी अभियान एवं विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा सत्र के प्रथम दिन राजधानी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में अपने मुद्दों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास किसानों द्वारा किया जा रहा है।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, दुर्ग (छ.ग.)

पता-नया बस स्टैण्ड के पीछे, दुर्ग

फोन एवं फैक्स नम्बर 0788-2322148

Email ID - durgmc2017@gmail.com

-:: निविदा संशोधन सूचना ::-

क्रमांक/221/लो.क.वि.अ./2024 **दुर्ग, दिनांक 13-12-2024**

कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग के द्वारा जारी मेनुअल निविदा सूचना क्रमांक/178/लो0क0वि0/2024-25 दुर्ग दिनांक 02.12.2024 (कार्य संख्या 11) एवं क्रमांक/208/लो0क0वि0/2024-25 दुर्ग दिनांक 02.12.2024 (कार्य संख्या 6) को जारी किया गया था जो कि निम्नानुसार है।:-

क्र.	तिथियों का विवरण	पूर्व में जारी	संशोधन अनुसार
01	निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	09.12.2024	09.12.2024
02	निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि	11.12.2024	16.12.2024
03	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	13.12.2024	20.12.2024 सायं 4.00 बजे तक
04	निविदा खोलने की तिथि	17.12.2024	20.12.2024 सायं 4.30 बजे

नगर पालिक निगम, दुर्ग के द्वारा जारी मेनुअल निविदा सूचना क्रमांक/647/ लो0क0वि0/2024-25 दुर्ग दिनांक 02.12.2024 (कार्य संख्या 7) एवं को जारी किया गया था जो कि निम्नानुसार है।:-

क्र.	तिथियों का विवरण	पूर्व में जारी	संशोधन अनुसार
01	निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	09.12.2024	09.12.2024
02	निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि	11.12.2024	16.12.2024
03	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	17.12.2024	20.12.2024 सायं 4.00 बजे तक
04	निविदा खोलने की तिथि	17.12.2024	20.12.2024 सायं 4.30 बजे

कार्यपालन अभियंता

नगर पालिक निगम, दुर्ग

देश की सबसे बहादुर पुलिस बलों में से है छत्तीसगढ़ पुलिस- अमित शाह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति कलर अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी जवानों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस अवार्ड का मिलना किसी भी राज्य के लिए गर्व का विषय है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहुत कम समय में ये अवार्ड हासिल किया है। शाह ने कहा कि वे पिछले 5 साल से नक्सलियों के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आपके अदम्य साहस, शौर्य और जज्बा को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस देश के बहादुर से बहादुर पुलिस वालों में से एक है। छत्तीसगढ़ के 25 साल में प्रवेश करने से पहले ही या रजत जयंती से पहले ही छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड मिला है। यह आपकी लगन और परिश्रम का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर क्षेत्र में चौतरफा कार्य कर रही है। चाहे देश को नशामुक्त करना हो या देश से नक्सलियों को मुक्त करने का अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस ने हर जगह दोहरे नहीं बल्कि फर्स्ट दर्जे के हिसाब से काम किया है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ तो उसे समय 256 रियासतें थी। देश को एक करना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया यह उनके अदम्य साहस का परिचय था। सरदार वल्लभ भाई के अधूरे कार्य को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। धारा 370 को खत्म कर आज कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। आज पूरा देश और मैं सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा हूं।

उन्होंने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के सपने को साकार किया और छत्तीसगढ़ राज्य बना। पहले ही चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया और 15 साल तक रमन सिंह के कार्यकाल में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की गई और आज भी कार्रवाई जारी है। विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। जनता की ओर से बीजेपी सरकार पर भरोसा जताए जाने पर शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले ही छत्तीसगढ़ नक्सल से मुक्त होगा। जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, वैसे ही पूरे देश को नक्सल मुक्त किया जाएगा।

शाह ने कहा कि 1 साल में 287 नक्सली न्यूट्रलाइज किया गया। करीब 1000 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 837 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार बदलने से नक्सल ऑपरेशन को कितनी सफलता मिली है। टॉप 14 नक्सली मारे गए। चार दशक में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच मृत्यु का आंकड़ा 100 से कम ले जाने का काम किया गया है। पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में नक्सलियों पर नकेल कसी गई। नक्सली मामलों में 73 प्रतिशत की कमी आई।

छत्तीसगढ़ पुलिस जहां नक्सलियों की सफाई करने में लगी हुई है। वहीं कोरोना में मैंने देशभर के सभी पुलिस के रिव्यू किया था उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोरोना के समय देशभर में सबसे अच्छा काम किया। कोरोना को मात देने में बेहतर काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सलियों से पुनर्वास नीति का लाभ लेने के लिए आह्वान किया और कहा कि शस्त्र त्याग कर बेहतर पुनर्वास नीति का लाभ लें। सरेंडर करने के बाद नक्सली पुनर्वास पॉलिसी का लाभ उठाइए।

छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड से किया सम्मानित

छत्तीसगढ़ प्रवास के पहले दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचकर राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड-2024 में शिरकत की और घुड़सवार दस्ते के साथ परेड ग्राउंड में पुलिस प्लाटून की सलामी ली। महिला पुलिस बैंड ने इस दौरान मनमोहक बैंड की प्रस्तुति दी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, राज्य गृहमंत्री विजय शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ पुलिस को 24 वर्षों के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया।

आज शाम हो सकता है फडणवीस सरकार का मंत्रीमंडल विस्तार

33 साल बाद नागपुर में शपथ ग्रहण, बन सकते हैं रवींद्र चव्हाण महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष

नागपुर (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट विस्तार करेंगे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे नागपुर विधान भवन में होगा।

महाराष्ट्र में 33 साल बाद कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण राज्य की उप-राजधानी में होने जा रहा है। इससे पहले 21 दिसंबर 1991 को कांग्रेस के CM सुधाकरराव नाइक के मंत्रिमंडल का विस्तार नागपुर में हुआ था। आज कैबिनेट विस्तार में 30-32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें भाजपा के 20-21 विधायक मंत्री बन सकते हैं। शिवसेना को 11-12 और NCP-अजित गुट को 9-10 मंत्री पद मिल सकते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले फडणवीस कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। उन्हें भाजपा अध्यक्ष पद छोड़ना होगा। संभावना है कि महाराष्ट्र भाजपा की कमान रवीन्द्र चव्हाण को दी जा सकती है।

फडणवीस मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे

भाजपा : चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, जय कुमार रावल, पंकजा मुंडे, पंकज भोयर, राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा, शिवेंद्र राजे भोंसले, मेघना बोर्डिकर, माधुरी मिसाल।

शिवसेना शिंदे गुट: संजय शिरसाठ, उदय सामंत, शंभुराजे देसाई, गुलाबराव पाटिल, भारत गोगवाले, संजय राठौड़, आशीष जयसवाल, प्रताप सरनाइक, योगेश कदम, प्रकाश आबिट्कर।

NCP- अजित गुट: छगन भुजबल, अदिति तटकरे, नरहरि झिरवाल, बाबासाहेब पाटिल, हसन मुश्रिफ़ दत्तामामा भरणे, अनिल पाटिल।

सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट के संजय शिरसाठ को, BJP से चंद्रकांत पाटिल, जयकुमार रावल, नीतेश राणे को भी मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाया गया है। माधुरी मिसाल, पंकजा मुंडे, मेघना बोर्डिकर और शिवेंद्र सिंह राजे भोसले को भी फोन करके नागपुर बुलाया है। NCP से सना मलिक, नरहरि झिरवाल को भी फोन पहुंचा है। बीजेपी ने कुछ नए चेहरों को मौका देने का भी फैसला किया है। हालांकि वह अपने कोटे की 20 सीटों में कुछ सीटें खाली रख सकती है। इधर, शिवसेना ने 5 पुराने और 7 नए चेहरों को मौका दिया है।

सूत्रों के अनुसार भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। पार्टी ने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं, NCP को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है। गृह और वित्त मंत्रालय को लेकर सहमति न बनने की वजह से कैबिनेट विस्तार में देरी हुई है। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे गृह और वित्त मंत्रालय पर दावा कर रहे हैं। जबकि भाजपा गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। वित्त मंत्रालय पर अजित पवार दावा कर रहे हैं। शिंदे सरकार में गृह मंत्रालय तब के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के पास था। इसलिए एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं।

नागपुर में क्यों हो रहा शपथग्रहण

महाराष्ट्र में विधानसभा के दो भवन हैं, एक मुंबई और दूसरा नागपुर में। विधानसभा का बजट और मानसून सत्र मुंबई में होता है। जबकि शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से नागपुर में होना है। इसी वजह से शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के बजाय नागपुर में हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के इन भागों में शीतलहर का अलर्ट, बलरामपुर में 3 डिग्री रहा पारा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन तीनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही कई जिलों में शीतलहर के हालात हैं। 2 दिनों बाद प्रदेश के दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावना है। राजधानी रायपुर समिति प्रदेश घर में पिछले दो-तीन दिनों से लगातार ठंड पड़ रही है। रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। वहीं सबसे ठंड बलरामपुर जिला रहा है। यहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री दर्ज किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, 15 दिसंबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगले दो दिन में अधिक स्पष्ट होने और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में तमिलनाडु के तट की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में उत्तर से आ रही शुष्क हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं ठिठुरन का भी एहसास हो रहा है। ग्रामीण और आउटर इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ ठिठुरन के हालात हैं। मौसम एक्सपर्ट में बताया कि छत्तीसगढ़ में आगामी तीन दिनों तक मध्य और उत्तर भागों के जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तीन दिनों के बाद दक्षिणी भागों के जिलों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। वहीं 17 दिसंबर की रात और 18 दिसंबर की सुबह से दक्षिण भागों आकाश मेघमय रहने और एक दो जगह पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो जगह पर शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर में पिछले दो-तीन दिनों से लगातार ठंड पड़ रही है। रात का तापमान सामान्य से नीचे गिरा हुआ है। यहां शनिवार को न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम रहा। वहीं पेंड्रा रोड और दुर्ग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहा है।

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार
RO-42449/75

बस्तर ओलंपिक 2024
करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर

सुशासन का 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल

बस्तर ओलंपिक 2024

खेलों के जरिए
सुखद भविष्य
की ओर बढ़ता
बस्तर

श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

खेलेगा बस्तर
बढ़ेगा बस्तर

हमने बनाया है
हम ही सँवारेंगे

हमसे जुड़ने के लिए
Q.R. स्कैन करें

ChhattisgarhCMO
Visit us : DPRChhattisgarh

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
www.dprcg.gov.in

RO-42449/75

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950